'निवेश मित्र पोर्टल पर एक महीने में करें लंबित प्रस्तावों का निस्तारण'

NBT रिपोर्ट, लखनऊ : उद्यमियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिलने में आ रही अड़चनों को दूर करने की जिम्मेदारी अब औद्योगिक विकास मंत्री और शासन के उच्चाधिकारी संभालेंगे। उद्यमियों की समस्याओं के निपटारे के लिए हर महीने उद्यमी मित्रों और जीएम-डीआईसी के साथ बैठक होगी। इसके निर्देश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में दिए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री ने सभी उद्यमी मित्रों और जीएम-डीआईसी को निर्देश दिए

कि निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित सभी प्रस्तावों को एक महीने के भीतर निस्तारित किया जाए। इस दौरान मंत्री ने लखनऊ, प्रतापगढ़, अयोध्या, प्रयागराज समेत कई जिलों के उद्यमी मित्रों के साथ संवाद भी किया।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि ऑनलाइन अनुमोदन में तेजी लाने और प्रक्रियाओं को ज्यादा पारदर्शी बनाने से निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ेगा। मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि बंद मिलों, कारखानों और चीनी मिलों की भूमि की पहचान कर उनका उपयोग लैंडबैंक के रूप में किया जाना चाहिए। अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी निवेशक को विभाग के चक्कर न लगाना पड़े।